

भारत सरकार
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय
लोक सभा
लिखित प्रश्न सं. 313
जिसका उत्तर 08.12.2022 को दिया जाना है
राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण

313. श्री चंद्र शेखर साहू:
श्री गिरीश भालचन्द्र बापट:

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने वर्तमान वित्तीय वर्ष में प्रतिदिन 40 किमी राष्ट्रीय राजमार्ग (एनएच) के निर्माण का लक्ष्य निर्धारित किया है और यदि हां, तो इस लक्ष्य को अब तक कितना प्राप्त कर लिया गया है;

(ख) क्या सरकार ने ऐसी परियोजनाओं की पहचान की है जो भारतीय अर्थव्यवस्था को संभारतंत्रीय दक्षता प्रदान करने में सहायक हैं और यदि हां, तो विशेषकर महाराष्ट्र और ओडिशा में तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने ऐसे भीड़-भाड़ वाले स्थानों और आर्थिक केंद्रों की पहचान की है, जहां भारी यातायात प्रवाह है ताकि सड़क संपर्क को कुशल और सुचारू बनाया जा सके;

(घ) यदि हां, तो विशेषकर महाराष्ट्र और ओडिशा में तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ड.) क्या सरकार का कुछ राष्ट्रीय राजमार्ग और एक्सप्रेसवे का प्रतिभूतिकरण करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री
(श्री नितिन जयराम गडकरी)

(क) मंत्रालय ने 2022-23 के दौरान 12,200 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण का लक्ष्य रखा है, जिसके मुकाबले नवंबर, 2022 तक 4766 किलोमीटर का निर्माण किया जा चुका है।

(ख) भारतमाला परियोजना के तहत, देश में राजमार्गों/एक्सप्रेसवे, जो भारत की अर्थव्यवस्था को रसद दक्षता की सुविधा प्रदान करते हैं, के विकास के अलावा 35 मल्टी मॉडल रसद पार्क (एमएमएलपी) विकसित किए जाने हैं। ये एमएमएलपी प्रमुख कार्गो समेकन और वितरण हब के रूप में कार्य करेंगे। देश में 35 एमएमएलपी के साथ भारतमाला परियोजना के क्रियान्वयन से लॉजिस्टिक दक्षता में और वृद्धि होने की

उम्मीद है। महाराष्ट्र और ओडिशा सहित -भारतमाला परियोजना के तहत स्वीकृत 35 एमएमएलपी की सूची राज्य वार अनुबंध । के रूप में संलग्न है।

(ग) और (घ) भारतमाला परियोजना के तहत ऐसे 191 भीड़भाड़ के बिंदुओं को पूरे नेटवर्क पर चिन्हित किया गया है। 191 चोक प्वाइंट्स में से 56 भीड़भाड़ बिंदुओं पर भीड़भाड़ कम करने की परियोजनाए पहले ही पूरे हो चुकी हैं और 83 भीड़भाड़ स्थानों पर भीड़भाड़ कम करने की परियोजनाए कार्यान्वित की जा रही हैं। शेष 52 भीड़-भाड़ वाले बिंदुओं पर काम वित्तीय वर्ष 2024-25 तक निर्माण के लिए दिया जाएगा। महाराष्ट्र और ओडिशा राज्य सहित पूरे देश में भीड़-भाड़ वाले बिंदुओं और इसमें सुधार की स्थिति अनुबंध ॥ के रूप में संलग्न है।

(ड) एनएच और एक्सप्रेसवे को सुरक्षित करने के लिए अभी तक किसी प्रस्ताव को मंजूरी नहीं दी गई है ।

राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण के संबंध में श्री चंद्र शेखर साहू, श्री गिरीश भालचन्द्र बापट द्वारा पूछे गए दिनांक 08.12.2022 के लोकसभा प्रश्न सं. 313 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

अनुमोदित एमएमएलपी की राज्यवार सूची

क्र.सं.	स्थान	राज्य
1	दिल्ली-एनसीआर (दिल्ली, गुडगांव, गाजियाबाद, फरीदाबाद, नोएडा)	दिल्ली/हरियाणा/उत्तर प्रदेश
2	मुंबई (मुंबई, मुंबई उपनगर, जेएनपीटी, मुंबई पोर्ट, रायगढ़ जिला)	महाराष्ट्र
3	उत्तर गुजरात (अहमदाबाद और वडोदरा)	गुजरात
4	हैदराबाद	तेलंगाना
5	दक्षिण गुजरात सुरत	गुजरात
6	दक्षिण पंजाब (लुधियाना, संगरूर, पटियाला)	पंजाब
7	उत्तरी पंजाब (अमृतसर, जालंधर, गुरुदासपुर)	पंजाब
8	जयपुर	राजस्थान
9	बैंगलोर	कर्नाटक
10	पूणे	महाराष्ट्र
11	अनंतपुर	आंध्र प्रदेश
12	चेन्नई	तमिलनाडु
13	नागपुर	महाराष्ट्र
14	इंदौर	मध्य प्रदेश
15	पटना	बिहार
16	कोलकाता	पश्चिम बंगाल
17	अंबाला	पंजाब
18	वलसाड	गुजरात
19	कोयंबटूर	तमिलनाडु
20	जगतसिंहपुर	ओडिशा
21	नासिक	महाराष्ट्र
22	गुवाहाटी	असम
23	कोटा	राजस्थान
24	पणजी	गोवा
25	हिसार	हरियाणा
26	विशाखापत्तनम	आंध्र प्रदेश
27	भोपाल	मध्य प्रदेश
28	सुंदरगढ़	ओडिशा
29	भटिंडा	पंजाब

30	एक प्रकार का हंस	हिमाचल प्रदेश
31	राजकोट	गुजरात
32	रायपुर	छत्तीसगढ़
33	जम्मू	जम्मू और कश्मीर
34	कांडला	गुजरात
35	कोचीन	केरल

राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण के संबंध में श्री चंद्र शेखर साहू, श्री गिरीश भालचन्द्र बापट द्वारा पूछे गए दिनांक 08.12.2022 के लोकसभा प्रश्न सं. 313 के भाग (ग) और (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

महाराष्ट्र और ओडिशा राज्य सहित देश भर में भीड़-भाड़ वाले स्थानों और उनमें सुधार की राज्य-वार सूची और उनमें सुधार

राज्य	पूरा हुआ	सौंपा गया	अभी तक सौंप जाना है	कुल योग
आंध्र प्रदेश	2	2	3	7
असम	-	3	1	4
बिहार	-	4	-	4
छत्तीसगढ़	1	-	4	5
दिल्ली	2	-	-	2
गुजरात	3	6	2	11
हरयाणा	-	2	1	3
जम्मू और कश्मीर	-	1	-	1
झारखंड	1	2	1	4
कर्नाटक	4	7	5	16
केरल		1	4	5
मध्य प्रदेश	6	5	7	18
महाराष्ट्र	10	21	4	35
मणिपुर	-	-	1	1

मेघालय	-	-	1	1
मिजोरम	-	-	1	1
नगालैंड	-	-	1	1
ओडिशा	-	4	4	8
पंजाब	3	3	1	7
राजस्थान	7	6	1	14
तमिलनाडु	2	7	5	14
तेलंगाना	1	1	-	2
उत्तर प्रदेश	9	2	2	13
पश्चिम बंगाल	5	6	3	14
कुल योग	56	83	52	191
